भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.-447

उत्तर देने की तारीख-02.02.2026

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) 2025-26

†447. **श्रीमती भारती पारधी:**

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) 2025-26 के अनुसार कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों का कुल प्रतिशत कितना है और पिछले वर्षों में उनमें कितना सुधार हुआ है;

(ख) अनिवार्य डिजिटल अवसंरचना की कमी वाले स्कूलों, विशेषकर उन कम डिजिटल पहुंच वाले क्षेत्रों में, का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार तथा विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उपकरण की कमी, कनेक्टिविटी की समस्या, अनुरक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण जैसे डिजिटल उपकरणों को अपनाने में स्कूलों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) डिजिटल अवसंरचना में सुधार अधिगम परिणामों या छात्रों के स्कूल में बने रहने से किस प्रकार संबद्ध हैं; और

(ङ.) क्या बेहतर डिजिटल उपकरणों वाले स्कूलों में छात्रों के स्कूल में बने रहने की दर बेहतर है, स्कूल छोड़ने की दर कम है या परिवर्तनकाल दरें बेहतर हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): यूडाइज+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं वाले स्कूलों का प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques. पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासन के अधीन हैं। पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए कई व्यापक डिजिटल शिक्षा पहल की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल लागू करता है। इस पहल का उद्देश्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप और प्रशिक्षण संसाधनों सहित शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों का समर्थन करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत अंतराल का आकलन करने के बाद राज्य की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती है।

डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए, विशेष रूप से महामारी के बाद शिक्षा में, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल जिसके तहत शिक्षा के लिए बहुआयामी पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया जाता है। इस पहल के प्रमुख घटक दीक्षा - देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा, कक्षा 1 से 12वीं तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने हेतु 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल, डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री के प्रसार के लिए ई-पाठशाला पहल, प्रत्यक्ष रूप से जादुई पिटारा की सहायता और उसे पूरा करने के लिए ईजादुई पिटारा डिजिटल ऐप, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आभासी प्रयोगशाला पर एक वर्टिकल बनाया गया है दीक्षा पर - आस्क दीक्षा (पुस्तकों के साथ चैट), वीडियो कीवर्ड खोज, रीड अलाउड और एआई-बेस ट्रांजिशन, पर्सनलाइज़ एडेप्टिव लर्निंग (पीएएल) के लिए उपयोगी जैसे विभिन्न एआई विशेषताएं उपलब्ध हैं।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल अवसंरचना मंच है, जिसके अंतर्गत सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेटिक पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) उपलब्ध कराई जाती हैं। कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता घटक शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन/करार करने और उन सभी सरकारी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई थी, जिनके पास कंप्यूटिंग उपकरण हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इंटरनेट प्रभारों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी प्रयोगशालाओं/स्मार्ट कक्षाओं के लिए जारी किए जा रहे आवर्ती प्रभारों अथवा समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी की जा रही प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) निधियों से या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की निधियों से पूरा किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट 2025 के भाग के रूप में, दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता के लिए जगह देने के लिए, 300 से अधिक वर्चुअल लैब बनाई गई हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय पहल भी शुरू की है। निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। निष्ठा ऑनलाइन को अक्टूबर, 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। निष्ठा प्रशिक्षण को वर्ष 2021-22 में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद, निष्ठा ने मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का भी विस्तार किया।

(ड़): यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधाएं, प्रतिधारण दर, ड्रॉपआउट दर और अंतरण दर वाले स्कूलों का प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques. पर उपलब्ध है।

******